

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2022 (डूंगरपुर आर्डर)

नाथू पिता हलु, जाति भील, निवासी सागवाडा, हाल चितरी, फला झिझवा,
तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सागवाडा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम -1955 विरुद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
दिनांक 19.09.2022 प्र.सं. 30/2021
---/---

- उपस्थित(वक्तबहस)
- 1- श्री संजीव भटनागर अभिभाषक अपीलान्ट
 - 2- श्री मनीष पटेल अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
 - 3- श्री पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 07-03-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 5460 रकबा 0.5177 हैक्टर भूमि मौजा सागवाडा में स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर पीढी दर पीढी से उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है तथा संवत् 2053 से 2056 में उसका नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है। वर्तमान में भूमि बिलानाम हो अप्रार्थी संख्या 1 नगर पालिका सागवाडा के खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी नंबर 5460 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा किस्म मगरी पर प्रार्थी का कब्जा 30-40 वर्षों से चला आ रहा है एवं नियमन हेतु संभागीय आयुक्त में आवेदन दिनांक 01-07-2019 को दिया गया था, जिस पर संभागीय आयुक्त ने जिला कलक्टर, डूंगरपुर



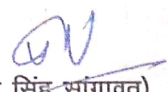
(Handwritten signature)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

खातेदारी में दर्ज होने से अपीलान्त/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी का खातेदार है तथा खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी अपीलान्त/प्रार्थी नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह स्वीकृत स्थित है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार हैं। अपीलान्त/प्रार्थी विवादित आराजी पर अपना पुराना कब्जा बताते हैं एवं इस आधार पर रेकार्डेड खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाहते हैं, किन्तु मात्र पुराने कब्जे के आधार पर रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19-09-2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 07-03-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

